



जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन-सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञापित)

राजस्थान डिस्कॉम्स को 3000 करोड़ रुपए की सहायता के प्रस्ताव
पर विश्व बैंक की टीम के साथ हुई सकारात्मक चर्चा

जयपुर, 13 जनवरी। राजस्थान के विद्युत वितरण तंत्र को विकसित करने तथा प्रदेश की तीनो विद्युत वितरण निगमों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार विश्व बैंक से उचित शर्तों पर 3000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की सम्भावनाएं तलाश कर रही है।

राज्य सरकार के इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए विश्व बैंक प्रतिनिधिमण्डल ने 12-13 जनवरी, 2016 को राज्य के ऊर्जा विभाग के आला अधिकारियों और विद्युत वितरण निगमों के अधिकारियों से प्रारम्भिक चर्चा की।

दो दिन की बैठक में दोनो ही पक्षों ने वित्तीय सहायता पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। अब इस मामले पर दोनों पक्ष जनवरी के अंतिम सप्ताह एवं फरवरी के प्रथम सप्ताह में दुबारा विस्तार से चर्चा करेंगे और सभी बिन्दुओं पर सहमति बनाने का प्रयास करेंगे।

चर्चा के दौरान विश्व बैंक के दल द्वारा राजस्थान डिस्कॉम्स को तकनीकी सहायता देने का प्रस्ताव रखा, जिसके तहत 4 क्षेत्रों में तकनीकी सहायता के लिए सहमति हुई।

ऐसी संभावना है कि फरवरी अन्त तक 3000 करोड़ रुपए की सहायता के मामले पर विश्व बैंक एवं राज्य सरकार दानों के सहमत होने की संभावना है, जिसके अन्तर्गत इसकी प्रथम किश्त मार्च, 2016 के अन्त तक मिलने की भी संभावना है।

बैठक में ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री संजय मल्होत्रा, तीनों विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष श्री भास्कर ए. सावंत, जोधपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक, निदेशक-वित्त, निदेशक -तकनीकी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।